

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक: 189/स.सा.प्र.वि./2020

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/04/2020

प्रति,

1. समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,
2. समस्त संभागायुक्त
3. समस्त कलेक्टर
4. समस्त विभागाध्यक्ष

विषय:— नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत।

संदर्भ:— गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 15/04/2020 तथा दिनांक 16/04/2020


—00—

संदर्भित आदेश द्वारा राज्य शासन को नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति बाबत अधिकृत किया गया एवं इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2/ अतः इस संबंध में प्रदेश में चिन्हित जिले/हॉटस्पॉट्स के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से संलग्न निर्देशों अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

3/ पूर्व में अप्रभावित जिले/क्षेत्र के हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा संपूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।


(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.कमांक: 190 /स.सा.प्र.वि./2020
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 16/04/2020

1. भारत सरकार के केबिनेट सचिव,
2. गृह सचिव, भारत सरकार,
3. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
4. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईट रायपुर,
6. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
8. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
9. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
10. प्रमुख आयकर आयुक्त, रायपुर, छत्तीसगढ़,
11. मंडल रेल प्रबंधक, रायपुर, बिलासपुर,
12. चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रायपुर,
13. महालेखाकार, ऑडिट/लेखा
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
16. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
17. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

KPF
सचिव, 16/4/20

सामान्य प्रशासन विभाग

कोरोना वायरस महामारी COVID 19 के संक्रमण को रोकने हेतु भारत सरकार के विभागों, राज्य सरकारों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों के संबंध में समेकित एवं संशोधित दिशा-निर्देश।
(गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-1(A), दिनांक 15/04/2020 अनुसार)

1. लॉकडाउन को बढ़ाये जाने के साथ 3 मई 2020 तक निम्न गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:-
 - i. सभी घरेलु एवं अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाओं से आवागमन, छूट: पैरा-4 (ix) में उल्लेखित उद्देश्यों हेतु तथा सुरक्षागत कारणों से
 - ii. यात्री रेल के माध्यम से आवागमन, छूट: सुरक्षागत कारणों से
 - iii. बसों के माध्यम से परिवहन
 - iv. मेट्रो रेल सेवाएं,
 - v. व्यक्तियों का अंतरराज्यीय एवं अंतर्जिला परिवहन, छूट: चिकित्सीय कारणों से एवं इन निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त गतिविधियों हेतु
 - vi. सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे।
 - vii. इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
 - viii. इन निर्देशों के अंतर्गत विशिष्ट अनुमति प्राप्त गतिविधियों को छोड़कर सभी हास्पिटलिटी सेवाएं बंद रहेगी।
 - ix. टैक्सी (आटोरिक्शा एवं साइकिल रिक्शा सहित) तथा कैब एग्रीगेटर सेवाएं
 - x. सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग काम्प्लेक्स, मॉल, जिम, खेलकुद काम्प्लेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला, बार एवं सभागार, असेम्बलीहॉल एवं इस प्रकार के स्थान।
 - xi. सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/खेल-कुद/शैक्षिक/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक एवं अन्य सामूहिक आयोजन।
 - xii. सभी धार्मिक स्थल/पूजा के स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सामूहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
 - xiii. अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
2. हॉटस्पॉट्स एवं कंटेन्मेंट जोनो में दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन :-
 - i. हॉटस्पॉट्स, ऐसे क्षेत्र या ऐसे क्लस्टर जिनमें कोरोना वायरस का संक्रमण वृहद स्तर पर फैला हो, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप चिन्हित होंगे।
 - ii. इन हॉटस्पॉट्स में जिला प्रशासन द्वारा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेन्मेंट जोन सीमांकित किये जायेंगे।
 - iii. इन कंटेन्मेंट जोन के भीतर इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कंटेन्मेंट जोन क्षेत्र की परिधी में व्यक्तियों के आने-जाने पर कठोर नियंत्रण रखा जायेगा ताकि केवल अत्यावश्यक सेवाओं (कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य आपातकाल सेवाओं सहित) तथा शासकीय कार्य हेतु वांछित व्यक्तियों का मात्र आवागमन हो। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा कठोरता से पालन किया जाये।

3. 20 अप्रैल 2020 से चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियां :-

- i. जनता की समस्याओं को कम करने हेतु चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति 20 अप्रैल से होगी। जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इन चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियों को क्रियान्वित कराया जायेगा। इन चिन्हित अतिरिक्त गतिविधियां की अनुमति देने से पूर्व जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्ट्रीयों एवं अन्य स्थापनों में सोशल डिस्टेंस एवं अन्य तैयारी संबंधी व्यवस्था निर्धारित प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार हो गई हो।
- ii. इन समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के निम्न पैरा 5 से 20 में इन चिन्हित अनुमति प्राप्त गतिविधियों की जानकारी दी गई।

4. लॉकडाउन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन :-

- i. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाये तथा इनमें किसी प्रकार की ढील न दी जाये।
- ii. स्थानीय आवश्यकतानुसार इन दिशा-निर्देशों में दिये गये प्रावधानों को जिला दंडाधिकारी द्वारा और अधिक कठोर किया जा सकता है।

5. सभी स्वास्थ्य सेवाएं शासकीय एवं निजी (आयुष सहित) चालू रहेंगी, जैसे :-

- i. अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं
- ii. डिस्पेंसरी, दवा दुकान, कैमिस्ट, फार्मसी (जन औषधी केन्द्र सहित) एवं मेडिकल इक्युपमेंट दुकान
- iii. मेडिकल लैब एवं कलेक्शन सेंटर
- iv. दवा एवं चिकित्सीय रिसर्च लैब, कोरोना वायरस रिसर्च कर रहे संस्थान
- v. वर्टेनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, दवा एवं टीकों की बिक्री एवं सप्लाई
- vi. अधिकृत निजी संस्थान जो कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हो जैसे-होमकेयर, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेवाएं, सप्लाई चेन जो अस्पतालों में सहयोगी सेवाएं दे रहे हों।
- vii. दवा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन निर्माण युनिट तथा इनकी पैकेजिंग, कच्चा माल एवं अंतरिम उत्पाद बनाने वाली ईकाइयां
- viii. स्वास्थ्य/मेडिकल अधोसंरचना का निर्माण, एम्बुलेंस निर्माण
- ix. अंतरराज्यीय एवं राज्य के भीतर सभी चिकित्सीय एवं वर्टेनरी मानव संसाधन, वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य अस्पताल सेवाओं के व्यक्तियों का आवागमन एवं एम्बुलेंस का आवागमन।

6. कृषि एवं संबंधित गतिविधियां :-

A. सभी कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियां संपूर्णतः संचालित रहेंगी जैसे:-

- i. किसानों द्वारा कृषि गतिविधियां तथा कृषि मजदूरों द्वारा खेत में कृषि कार्य
- ii. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेन्सीयों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एजेन्सीयां
- iii. मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडीयां एवं उपमंडीयां, किसानों या किसानों के समुह (एफपीओ) से निजी क्षेत्र द्वारा सीधे कृषि उत्पाद क्रय प्रक्रिया, ग्राम स्तर से विकेन्द्रीकृत क्रय-विक्रय
- iv. कृषि मशीनरी विक्रय, इससे संबंधी स्पेयर पार्ट एवं मरम्मत की दुकाने (सप्लाई चेन) खुली रहेंगी

- v. कृषि मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर
- vi. खाद/उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय
- vii. फसल बोआई एवं कटाई के संबंध में कम्बाईन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि/हार्टिकल्चर मशीनरी उपकरणों का राज्य के भीतर एवं अंतरराज्यीय परिवहन
- viii. वनक्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वनवासियों द्वारा लघुवनोपज/गैर-काष्ठ वन उत्पाद का संग्रहण, हार्वेस्टिंग तथा प्रसंस्करण
- B. मछली पालन – निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी:-
 - i. मछली पालन संबंधी समस्त गतिविधियां/एक्वाकल्चर उद्योग (जल कृषि), पूरक आहार प्रदाय एवं मरम्मत, मत्स्य उत्पादन, प्रसंस्करण, कोल्डचेन, विक्रय एवं मार्केटिंग,
 - ii. हैचरी, पूरक आहार उत्पादन युनिट, व्यवसायिक उत्पादन,
 - iii. मछली/झींगा के भंडारण एवं परिवहन, मछली बीज/ पूरक आहार एवं इन सभी गतिविधियों से जुड़े हुए श्रमिक।
- C. बगान संबंधी निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी:-
 - i. चाय, कॉफी एवं रबड़ बगान, अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मियों सहित
 - ii. चाय, कॉफी रबड़ एवं काजू की प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बिक्री अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मियों सहित
 - iii. बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों के बगान में कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग एवं बिक्री
- D. पशुपालन संबंधी निम्न गतिविधियां संचालित रहेंगी:-
 - i. दुध एवं दुध उत्पादों के दूध के संग्रहण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग से लेकर वितरण/बिक्री तक सप्लाय चैन
 - ii. पशु फार्म, कुक्कुट पालन एवं हैचरी तथा पशुपालन गतिविधियां
 - iii. जानवरों के चारे के निर्माण संबंधित युनिट कच्चे माल की आपूर्ति जैसे – मक्का एवं सोया
 - iv. पशु गृह जैसे – गौशालाओं का संचालन
7. वित्तीय क्षेत्र: निम्नानुसार संचालित रहेगा:-
 - i. भारतीय रिजर्व बैंक, तथा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय मार्केट एवं संस्थाएं जैसे: NPCI, CCIL, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर तथा एकल प्रायमरी डीलर
 - ii. बैंक शाखाएं तथा एटीएम, बैंकिंग सेवाओं हेतु आई.टी. वेन्डर, बैंक मित्र तथा ए.टी.एम. संचालन व कौशल मैनेजमेंट एजेंसीयां
 - a बैंक शाखाओं को सामान्य कार्य दिवस में निर्धारित घंटों तक कार्य करने की अनुमति जब तक डीबीटी की राशि का आहरण पूर्ण हो।
 - b स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं तथा बैंक मित्रों को सोशल डिस्टेंशन कानून व्यवस्था तथा व्यवस्थित रूप से नगदी आहरण हेतु सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये।
 - iii. सेबी द्वारा अधिसूचित सेवाएं
 - iv. बीमा सेवाएं/बीमा कंपनियां
 - v. गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी) जैसे:- गृह निर्माण फाईनेंस कम्पनी तथा माइक्रो फाईनेंस संस्थान, न्यूनतम स्टाफ सहित
 - vi. सहकारी ऋण सोसायटियां
8. सामाजिक क्षेत्र: निम्नानुसार संचालित रहेगा:-
 - i. समाज कल्याण आवासीय संस्थाएं जो बच्चों/निःशक्तजन/मानसिक रूप से निःशक्त/बेघर/वरिष्ठ नागरिक/महिलाओं/विधवाओं की देख-रेख हेतु संचालित हों,
 - ii. आबजरवेशन होम, आफटर केयर होम तथा किशोर गृह
 - iii. सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था न्यूनतम स्टाफ सहित, EPFO द्वारा पेंशन एवं प्रॉविडेन्ट फंड की सेवाएं

- iv. आंगनबाड़ियों का संचालन – खाद्य पदार्थ एवं पोषण सामग्री का हितग्राहियों जैसे कि बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को द्वार प्रदाय के माध्यम से 15 दिन में एक बार वितरण, परंतु हितग्राही आंगनबाड़ी में उपस्थित नहीं होंगे।
9. ऑनलाईन शिक्षण/डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए :-
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे।
 - यद्यपि इन संस्थानों से यह अपेक्षित है कि वह शैक्षणिक कार्य ऑनलाईन माध्यम से जारी रखे।
 - शैक्षणिक कार्य हेतु दूरदर्शन एवं अन्य एजुकेशनल चैनलों का उपयोग अधिक से अधिक किया जाए।
10. मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी :-
- शोसल डिस्टेंसिंग तथा चेहरे पर मास्क के अनिवार्य पालन के साथ मनरेगा कार्यों की अनुमति होगी।
 - मनरेगा के अंतर्गत सिंचाई तथा जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
 - अन्य केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन जारी रह सकता है तथा मनरेगा के साथ अभिसरण उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।
11. पब्लिक यूटिलिटी : निम्न सेवाएं संचालित रहेंगी :-
- ऑयल एवं गैस क्षेत्र के कार्य जैसे कि रिफाईनिंग, परिवहन, वितरण, भंडारण एवं खुदरा बिक्री उदाहरण स्वरूप पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी इत्यादि।
 - केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर विद्युत का उत्पादन, पारेक्षण तथा वितरण।
 - डाक सेवाएं, डाक घर सहित।
 - जल प्रदाय, साफ-सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र की सेवाएं स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि के माध्यम से
 - टेलीकाम एवं इंटरनेट सेवाओं को प्रदाय करने वाले सेवा प्रदाताओं का संचालन
12. राज्यों के भीतर एवं अंतर्राज्यीय माल परिवहन तथा उसकी लोडिंग व अनलोडिंग की निम्नानुसार अनुमति होगी :-
- समस्त माल परिवहन की अनुमति होगी।
 - रेलवे सेवाओं में माल एवं पार्सल ट्रेन संचालित होंगे।
 - एयरपोर्ट अंतर्गत एयरकारगो परिवहन तथा राहत एवं बचाव उड़ाने संचालित होंगी।
 - बंदरगाह एवं इंग्लैण्ड कंटेनर डिपो माल परिवहन तथा इस हेतु अधिकृत कस्टम क्लियरिंग एजेंट तथा फारवर्डिंग एजेंट संचालित होंगे।
 - शुष्क बंदरगाह अंतर्देशीय माल परिवहन हेतु संचालित होंगे जिसमें आवश्यक वस्तुओं, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य पदार्थ एवं चिकित्सीय सामग्री का परिवहन होगा।
 - सभी माल वाहक ट्रक एवं अन्य वाहनों को अधिकतम 2 वाहन चालक तथा 1 सहायक के साथ संचालन की अनुमति होगी बशर्ते वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस हो। माल डिलीवरी उपरांत खाली ट्रक को लौटने की तथा माल भरने हेतु जाने की अनुमति होगी।
 - ट्रकों के रिपेयर की दुकानें तथा राज मार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंस सहित संचालित हो सकेंगी।
 - रेलवे, एयरपोर्ट/एयरकारगो, बंदरगाह/जहाज, शुष्क बंदरगाह, इंग्लैण्ड कंटेनर डिपो में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी तथा ठेका श्रमिकों को इन संस्थानों के अधिकृत प्राधिकारी के अनुरोध पर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।

13. आवश्यक सामग्रियों के वितरण की अनुमति निम्नानुसार होगी :-

- i. आवश्यक सामग्रियों के सप्लाई चेन से संबंधित सभी इकाईयों, विनिर्माण, खुदरा एवं थोक में वितरण/बिक्री से संबंधित सभी दुकानों/गोदामों, डिपार्टमेंटल स्टोर तथा ई-कामर्स कंपनियों के संचालन हेतु, सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त पर, समय-सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति होगी।
- ii. दुकानें (किराना दुकान एवं आवश्यक सामग्रियों का विक्रय कर रही एकल दुकाने सहित), ठेले, एवं राशन दुकानें (पीडीएस सहित) जो खाद्य, एवं रोजमर्रा उपयोग की वस्तुएं (साबुन, हाथ धोने की सामग्री, बॉडीवाश, सैनिटाईजर, वाशिंग पाउडर, टूथपेस्ट, बैटरी सेल, चार्जर, शैम्पू, टिशुपेपर, सैनिटरी नैपकिन एवं पैड इत्यादि) फल एवं सब्जी, दूध एवं डेयरी उत्पाद विक्रय बूथ, पोल्ट्री, मीट, अण्डे, मछली, पशुचारा इत्यादि विक्रय कर रही हो उनको सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त पर समय-सीमा के बंधन के बिना संचालन की अनुमति होगी।
- iii. जिला प्रशासन लोगों को घर से बाहर न निकलने को प्रोत्साहित करने के लिए होम डिलीवरी को बढ़ावा दे सकता है।

14. वाणिज्यिक एवं निजी संस्थानों को संचालन की अनुमति निम्नानुसार होगी :-


- i. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसार, डीटीएच एवं केबल टीवी सेवाएं
- ii. आई. टी. एवं आई.टी. आधारित सेवाएं अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति पर
- iii. शासकीय गतिविधियों हेतु डाटा एवं कॉल सेन्टर
- iv. शासन द्वारा अनुमोदित ग्राम पंचायत स्तर पर सीएससी केन्द्र
- v. ई-कामर्स कंपनियों, ई-कामर्स कंपनियों द्वारा प्रयुक्त वाहनों को स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी पास के आधार पर संचालन की अनुमति होगी।
- vi. कुरियर सेवायें
- vii. कोल्ड स्टोर एवं भंडार गृह सेवाएं बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, कंटेनर डिपो, उत्पादन इकाईयां अथवा लाजिस्टिक्स चेन में अन्य स्थानों पर
- viii. निजी सुरक्षा सेवाएं एवं कार्यालय एवं रहवासी कालोनियों के संधारण सुरक्षा हेतु फेसिलिटी मेनेजमेंट सेवायें
- ix. होटल, होमस्टे, लॉज, मोटल जो कि फसे हुए व्यक्तियों/पर्यटकों मेडिकल तथा आवश्यक सेवाओं वाले स्टॉफ हेतु संचालित हो
- x. स्वतः कार्य करने वाले व्यक्तियों जैसे कि इलेक्ट्रीशन, मोटर मेकेनिक, आईटी रिपेयर, बर्दई इत्यादि की सेवायें

15. उद्योगों/औद्योगिक संस्थानों (शासकीय एवं निजी संस्थानों) को निम्नानुसार संचालन की अनुमति होगी :-

- i. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात् नगरीय निकायों की सीमा के बाहर संचालित उद्योगों को संचालन की अनुमति होगी
- ii. ऐसे औद्योगिक इकाईयां जो निर्धारित औद्योगिक क्षेत्रों जैसे इंडस्ट्रियल इस्टेट में स्थित हों तथा जिनमें व्यक्तियों के आने-जाने पर नियंत्रण रखा जा सके। ऐसे उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को यथासंभव उनके उद्योग के परिसर के भीतर अथवा लगे हुए स्थानों/भवनों में ही रखने की व्यवस्था इन निर्देशों के पैरा - 21 (ii) में निर्धारित एसओपी अनुसार करनी अनिवार्य होगी। इन श्रमिकों के आने-जाने की व्यवस्था संबंधित उद्योगों द्वारा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए की जाएगी।
- iii. ऐसी औद्योगिक इकाईयां जो आवश्यक सामग्रियों, दवाईयों, मेडिकल उपकरण, दवाओं के कच्चे माल इत्यादि का उत्पादन करती हो को अनुमति होगी।
- iv. खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात् नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो
- v. उत्पादन इकाईयां जिनमें उत्पादन प्रक्रिया निरंतर प्रकार की हो एवं उनका सप्लाई चेन

- vi. आईटी हार्डवेयर उत्पादन इकाई
- vii. कोयला उत्पादन, खनन, खनिज परिवहन एवं खनिज उत्पादन से जुड़ी विस्फोटक सप्लाई एवं अन्य सहायक गतिविधियों
- viii. पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली उत्पादन इकाईयां
- ix. जूट आधारित उत्पादन इकाईयां, सोशल डिस्टेंस के पालन तथा पृथक-पृथक पाली में उत्पादन की शर्त पर
- x. तेल एवं गैस रिफाईनरी/एक्सप्लोरेशन
- xi. ईट भट्टे जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर हो
- 16. निम्न निर्माण गतिविधियों संचालन की अनुमति होगी :-
 - i. ग्रामीण क्षेत्र में अर्थात नगरीय निकायों की सीमा के बाहर सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजना, भवन निर्माण, जल प्रदाय एवं स्वच्छता, विद्युत ट्रांसमिशन लाईनों का निर्माण, दूरसंचार हेतु ऑप्टिकल फाइबर एवं केबल डालने का कार्य एवं सभी प्रकार के उद्योग (एमएसएमई सहित) निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमति होगी तथा सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र निर्माण की परियोजनाओं में अनुमति होगी।
 - ii. नवीकरणीय उर्जा संबंधी परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति होगी
 - iii. नगरीय निकायों की सीमा के भीतर ऐसी निर्माण परियोजनाएं जहां पर श्रमिक साईट पर उपलब्ध हो तथा बाहर से लाने की आवश्यकता न हो।
- 17. निम्नानुसार व्यक्तियों के आने-जाने की अनुमति होगी :-
 - i. अपातकालीन सेवाओं जैसे मेडिकल, एमरजेंसी, वर्टनरी एवं आवश्यक सामग्री क्रय हेतु निजी वाहनों की अनुमति होगी। चौपहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा केवल पीछे की सीट में एक सवारी बैठाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहनों में केवल चालक को ही अनुमति होगी।
 - ii. छूट प्राप्त श्रेणियों एवं अनुमति प्राप्त क्षेत्र के व्यक्तियों को जिला प्रशासन द्वारा निर्देशानुसार कार्यस्थल से निवास तक परिवहन की अनुमति होगी।
- 18. भारत सरकार के कार्यालय, भारत सरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं के कार्यालय निम्नानुसार खुलेंगे :-
 - i. रक्षा, केन्द्रीय पुलिस बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन एवं अरली वारनिंग एजेंसियों, एन.आई.सी., एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केन्द्र एवं सीमा शुल्क कार्यालय बिना किसी बाधा के कार्य करेंगे।
 - ii. अन्य मंत्रालयों एवं विभागों एवं अधिनस्थ संस्थाओं के कार्यालय उपसचिव एवं उच्चतर स्तर के अधिकारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति तथा उससे निम्न स्तरों के अधिकारियों एवं स्टाफ के 33 प्रतिशत उपस्थिति के स्तर के साथ संचालित रहेंगे।
- 19. राज्य सरकार के कार्यालय, राज्यसरकार की अधीनस्थ संस्थाओं/स्वायत्त संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के कार्यालय निम्नानुसार खुलेंगे :-
 - i. पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन एवं जेल नगरीय निकायों की सेवायें बिना किसी बाधा के संचालित होंगी।
 - ii. राज्य सरकार के अन्य विभागों एवं अधिनस्थ संस्थाओं के कार्यालय के संबंध में पूर्व में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए आवश्यक लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा।
 - iii. जिला प्रशासन एवं कोषालय (जिसमें सम्मिलित है महालेखाकार के मैदानी कार्यालय) सीमित स्टॉफ सहित संचालित रहेंगे यद्यपि लोक सेवाओं के प्रदाय को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इस हेतु आवश्यक स्टॉफ तैनात किया जाएगा।

- iv. नई दिल्ली में स्थित राज्यों के आवासीय आयुक्त कार्यालय, केवल कोरोना संक्रमण नियंत्रण गतिविधियों के समन्वय तथा आंतरिक किचन व्यवस्था हेतु न्यूनतम स्टाफ सहित संचालित होंगे।
- v. वन कार्यालय: चिड़ीया घर, नर्सरी, वन्यप्राणी, वनों में अग्निशमन, वनों में पेट्रोलिंग हेतु आवश्यक वाहन/मानव संसाधन सहित
20. अनिवार्य क्वारंटीन में व्यक्तियों को रखने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:-
- ऐसे व्यक्तियों जिनको घर/निर्धारित स्थल पर एक निर्धारित अवधि हेतु स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा स्वास्थ्य अमले के माध्यम से क्वारंटीन में निर्देशित किया गया हो।
 - व्यक्तियों जिनके द्वारा क्वारंटीन का उल्लंघन किया जाए वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
 - क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों, जो 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आये, को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार मुक्त किया जाएगा।
21. उपरोक्त लॉकडाउन आदेशों के पालन हेतु निर्देशों :-
- सभी जिला मजिस्ट्रेट राष्ट्रीय कोरोना वायरस कोविड - 19 नियंत्रण निर्देशों जो संलग्नक-1 अनुसार हैं, का कठोरता से पालन सुनिश्चित करेंगे। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों तथा स्थापनाओं पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाए।
 - सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं, कार्यस्थल, कार्यालय इत्यादि कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निर्धारित मानक प्रक्रिया एसओपी, जो संलग्नक - 2 में व्यवस्थित है, अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करेंगे।
 - कोरोना नियंत्रण के इन कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में कार्यपालिक दंडाधिकारियों को क्षेत्र निर्धारित करते हुए इन्सीडेन्ट कमान्डर के रूप में तैनात करेंगे जो अपने निर्धारित क्षेत्र में निर्देशों के पालन हेतु समग्र रूप से जिम्मेदार होंगे। निर्धारित क्षेत्र में सभी विभागों के अधिकारी/कर्मचारी इन्सीडेन्ट कमान्डर के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करेंगे। आवश्यक मूवमेंट हेतु इन्सीडेन्ट कमान्डर द्वारा पास जारी किया जायेगा।
 - इन्सीडेन्ट कमान्डर विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल अधोसंरचना के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन, वस्तुएं एवं सामग्री बिना किसी रुकावट के उपलब्ध रहे।
 - इन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अनुमति प्राप्त अतिरिक्त गतिविधियां निर्देशों के अंतर्गत वांछित अनिवार्य आवश्यक तैयारी करने के उपरांत ही योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ की जाए। यह निर्देश 20 अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे।
22. दाण्डिक प्रावधान :-
- इन लॉकडाउन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे। इन दाण्डिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण संलग्नक- 3 पर दिया गया है।


 16/4/20
 (डॉ. कमलप्रीत सिंह)
 सचिव,
 सामान्य प्रशासन विभाग

COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश

राष्ट्रीय निर्देश जिला दंडाधिकारी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार अर्थदंड तथा दंडात्मक कार्यवाही के माध्यम से लागू किये जायेंगे।

सार्वजनिक स्थल

1. सभी सार्वजनिक एवं कार्य स्थलों पर चेहरे का ढका जाना अनिवार्य होगा।
2. सभी व्यक्ति जो सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थल एवं परिवहन के प्रभारी हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
3. कोई भी संस्था/सार्वजनिक स्थल का प्रबंधक पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव की अनुमति नहीं देगा।
4. विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे आयोजनों के लिए व्यक्तियों के एकत्रित होने संबंधी व्यवस्था जिला दंडाधिकारी द्वारा विनियमित किया जायेगा।
5. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना अर्थदंड के साथ दंडनीय होगा।
6. शराब, गुटका, तम्बाकू इत्यादि के विक्रय पर कड़ा प्रतिबंध होगा एवं थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।

कार्यस्थल

7. समस्त कार्यस्थलों पर थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा सुविधाजनक स्थान पर सैनिटाईजर की व्यवस्था की जाए।
8. कार्यस्थलों पर प्रत्येक पाली के मध्य 1 घंटे का अंतराल रखा जाए एवं सोशल डिस्टेंस के परिपालन के लिए कर्मचारियों के भोजना अवकाश के मध्य अंतराल रखा जाए।
9. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों तथा ऐसे व्यक्तियों जिनको कोई सह-रुग्णता हो तथा 5 वर्ष के कम आयु के बच्चों के पालकों को घर से कार्य करने प्रोत्साहित किया जाये।
10. आरोग्य सेतु एप का उपयोग करने सभी प्राइवेट एवं शासकीय कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए।
11. समस्त संस्थाएं पालियों के मध्य अपने कार्यस्थलों के सैनिटाईजेशन की व्यवस्था करेंगे।
12. बड़ी बैठकें प्रतिबंधित होंगी।

विनिर्माण ईकाइयां

13. सार्वजनिक सतहों की बार-बार सफाई तथा हाथों की अनिवार्य धुलाई के आदेश जारी किये जाए।
14. पालियों की ओवर-लैपिंग ना हो तथा कैटीन में सामाजिक दूरी के नियम के पालन में लंच के समय को आगे-पीछे रखा जाए।
15. अच्छे स्वच्छता की आदतों से भली-भांती परिचित कराने प्रशिक्षण एवं पर्याप्त सूचना प्रदान किया जाये।

कार्यालयों, कार्यस्थलों, फ़ैक्ट्रियों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

कार्यालयों, फ़ैक्ट्रियों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निम्नलिखित उपाय अपनाए जाए :

1. निम्नलिखित स्थानों को सम्मिलित करते हुए परिसर के समस्त क्षेत्रों को पूर्णरूपेण उपयोक्ता मैत्रीपूर्ण (user-friendly) निस्संक्रामक (Disinfectant) उपयोग करते हुए संक्रमण रहित किया जाए :
 - a. भवन का प्रवेश द्वार, कार्यालय इत्यादि
 - b. कैफ़ेटेरिया एवं कैंटीन
 - c. बैठक कक्ष, सम्मेलन हाल/उपलब्ध खुली जगहें/वरांडा/जगह का प्रवेशद्वार/बंकर/पोर्टा केबिन/भवन इत्यादि
 - d. उपकरण एवं लिफ्ट
 - e. वाशरूम, प्रसाधन, सिंक, पानी के स्थान इत्यादि
 - f. दीवारें तथा अन्य सतहें
2. बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए सार्वजनिक यातायात के साधनों पर निर्भर ना रहते हुए परिवहन की विशेष व्यवस्था बनाई जाए। ऐसे वाहनों की यात्री क्षमा का 30-40 % उपयोग की अनुमति दी जाये।
3. परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों एवं मशीनों को अनिवार्यतः स्प्रे कर सैनेटाईजर किया जाये।
4. कार्यस्थल पर आनेवाले तथा जानेवाले सभी व्यक्तियों की अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग की जाये।
5. सभी कामगारों का चिकित्सा बीमा कराया जाना अनिवार्य किया जाए।
6. हैण्डवाश एवं सैनिटाईजर, जो स्पर्शमुक्त प्रणाली युक्त हो तो बेहतर, का प्रावधान समस्त आगम एवं निर्गम द्वारों तथा सार्वजनिक स्थानों पर किया जाए। उपरोक्त वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई जाये।
7. कार्यस्थलों पर दो पालियों के मध्य 1 घंटे का समय अंतराल रखा जाए तथा सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भोजन अवकाश में भी समय अंतराल रखा जाये।
8. दस या अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने अथवा बैठकों को हतोत्साहित किया जाए। कार्यस्थल बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि में बैठने के लिए कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखी जाये।
9. लिफ्ट इत्यादि में 2 से 4 (क्षमता के अनुसार) व्यक्तियों को चढ़ने की अनुमति दी जाये।
10. ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
11. गुटका, तम्बाकू इत्यादि के उपयोग तथा थूकने पर सख्त प्रतिबंध होगा।
12. स्थल पर अनावश्यक आगंतुकों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
13. आस पास के अस्पताल एवं क्लिनिक, जो COVID-19 के उपचार के लिए अधिकृत हो को चिन्हित कर सूची कार्यस्थल पर हर समय उपलब्ध कराई जाये।

कमांक 40-3/2020- DM-1 (A)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

भारत में फंसे हुए विदेशी नागरिकों के ट्रांजिट हेतु व्यवस्था के लिए एसओपी/मानक प्रक्रिया

गृह मंत्रालय की जानकारी में यह तथ्य लाए गए हैं कि देश के विभिन्न स्थलों पर लॉकडाउन के कारण विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं। कुछ देशों की सरकारों द्वारा भारत सरकार को अपने नागरिकों को निकालने के लिए अनुरोध किया है।

2. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अन्य देशों से अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकरणवार विचार किया जायेगा। ऐसे प्रकरण जहां विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमति दी जाये निम्नानुसार मानक प्रक्रिया का पालन किया जाये:-

(1) चार्टर फ्लाईट की व्यवस्था नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमति एवं समन्वय से संबंधित देश की सरकार द्वारा की जायेगी।

(2) अपने देश को रवाना होने से पहले विदेशी नागरिकों की कोरोना संक्रमण संबंधी जांच निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार की जायेगी। केवल उन्हीं विदेशी नागरिकों को जाने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर उनका ईलाज निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये।

(3) विदेशी नागरिकों के रूकने के स्थान से प्रस्थान तक व्यवस्था संबंधित देश के स्थानीय दूतावास/वाणिज्य दूतावास द्वारा की जायेगी।

(4) विदेशी नागरिकों के प्रस्थान हेतु प्रयुक्त वाहन के ट्रांजिट पास हेतु अनुमति उस राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित विदेशी नागरिका रूके हुए हैं।

(5) उपरोक्त कंडिका-4 में उल्लेख अनुसार जारी ट्रांजिट पास के आधार पर परिवहन की अनुमति मार्ग में स्थित अन्य राज्यों द्वारा दी जाये।

क्रमांक 40-3/2020- DM-1 (A)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

क्वारंटीन में रखे गये व्यक्तियों को निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत, तथा कोरोना वायरस टेस्ट में निगेटिव आने पर मुक्त करने हेतु एसओपी/मानक प्रक्रिया

कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु तथा सावधानी के रूप में 15 फरवरी 2020 के उपरान्त अन्य देशों से भारत आए व्यक्तियों को शासकीय/शासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर क्वारंटीन में रखा गया था। ऐसे व्यक्तियों के संबंध में निर्धारित क्वारंटीन अवधि की समाप्ति उपरांत निम्नानुसार प्रोटोकॉल का पालन किया जाये:-

- (1) व्यक्ति/व्यक्तियों जिनका कोरोना टेस्ट निगेटिव हो, निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकॉल अनुसार क्वारंटीन स्थानों से मुक्त किया जाये। लेकिन यह समूह में क्वारंटीन में रखे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जहां पर एक भी व्यक्ति कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया हो।
- (2) क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों से अपेक्षित है कि वह अपने निवास, अथवा अपने परिवार/संबंधी/मित्रों अथवा अन्य स्थल जैसे:-हॉटल इत्यादि अपनी व्यवस्था से जायें।
- (3) क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों के वाहन हेतु ट्रांजिट पास की अनुमति उस राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में संबंधित व्यक्ति रूके हुए थे।
- (4) ट्रांजिट पास की अनुमति में मार्ग एवं समय सीमा निर्धारित की जाये जिसका पालन संबंधित क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों द्वारा किया जायेगा।
- (5) उपरोक्त कंडिका-4 में उल्लेख अनुसार जारी ट्रांजिट पास के आधार पर परिवहन की अनुमति मार्ग में स्थित अन्य राज्यों द्वारा दी जाये।
- (6) गंतव्य स्थल पर पहुंचने क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों को अपने निवास पर उपरान्त अतिरिक्त सावधानी के लिए और 14 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए स्वयं को होम क्वारंटीन निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार किया जाये।
- (7) क्वारंटीन से मुक्त व्यक्तियों का विवरण उनके गंतव्य स्थल सहित संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ फॉलोअप साझा किया जाये।

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 15th April, 2020

ORDER

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, has issued an Order dated 14th April, 2020 that the lockdown measures stipulated in the Consolidated Guidelines of Ministry of Home Affairs (MHA) for containment of COVID-19 epidemic in the country, will continue to remain in force upto 3rd May, 2020 to contain the spread of COVID-19 in the country.

Whereas, to mitigate hardship to the public, select additional activities will be allowed, which will come into effect from 20th April, 2020. However, these additional activities will be operationalized by States/ Union Territories (UTs)/ District Administrations based on strict compliance to the existing guidelines on lockdown measures. Before operating these relaxations, States/ UTs/ District Administrations shall ensure that all preparatory arrangements with regard to social distancing in offices, workplaces, factories and establishments, as also other sectoral requirements are in place. The consolidated revised guidelines incorporating these relaxations are enclosed;

Whereas, the consolidated revised guidelines will not apply in containment zones, as demarcated by States/ UTs/ District administrations. If any new area is included in the category of a containment zone, the activities allowed in that area till the time of its categorization as a containment zone, will be suspended except for those activities as are specifically permitted under the guidelines of Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India;

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(I) of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues directions to all the all Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/Union Territory Authorities for the strict implementation of enclosed consolidated revised guidelines.


15/04/2020
Union Home Secretary

To:

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
(As per list attached)

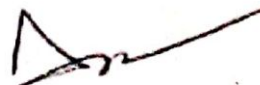
Copy to:

- i. All members of the National Executive Committee.
- ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

Consolidated Revised Guidelines on the measures to be taken by Ministries/ Departments of Government of India, State/ UT Governments and State/ UT authorities for containment of COVID-19 in the country

[As per Ministry of Home Affairs (MHA) Order No. 40-3/2020-DM-I (A) dated 15th April, 2020]

- 1. With the extension of the lockdown period, the following activities will continue to remain prohibited across the country until 3rd May, 2020:**
 - i. All domestic and international air travel of passengers, except for purposes enumerated in para 4 (ix), and for security purposes.
 - ii. All passenger movement by trains, except for security purposes.
 - iii. Buses for public transport.
 - iv. Metro rail services.
 - v. Inter-district and inter-State movement of individuals except for medical reasons or for activities permitted under these guidelines.
 - vi. All educational, training, coaching institutions etc. shall remain closed.
 - vii. All industrial and commercial activities other than those specifically permitted under these guidelines.
 - viii. Hospitality services other than those specifically permitted under these guidelines.
 - ix. Taxis (including auto rickshaws and cycle rickshaws) and services of cab aggregators.
 - x. All cinema halls, malls, shopping complexes, gymnasiums, sports complexes, swimming pools, entertainment parks, theatres, bars and auditoriums, assembly halls and similar places.
 - xi. All social/ political/ sports/ entertainment/ academic/ cultural/ religious functions/ other gatherings.
 - xii. All religious places/ places of worship shall be closed for public. Religious congregations are strictly prohibited.
 - xiii. In case of funerals, congregation of more than twenty persons will not be permitted.
- 2. Operation of guidelines in Hotspots and containment zones**
 - i. 'Hotspots', i.e., areas of large COVID-19 outbreaks, or clusters with significant spread of COVID-19, will be determined as per the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India (GoI).
 - ii. In these hotspots, containment zones will be demarcated by States/ UTs/ District administrations as per the guidelines of MoHFW.
 - iii. In these containment zones, the activities allowed under these guidelines will not be permitted. There shall be strict perimeter control in the area of the containment zones to ensure that there is no unchecked inward/ outward movement of population from these zones except for maintaining essential services (including medical emergencies and law and order related duties) and Government business continuity. The guidelines issued in this regard by MoHFW will be strictly implemented by State/ UT Governments and the local district authorities.



3. Select permitted activities allowed with effect from 20th April, 2020:

- i. To mitigate hardship to the public, select additional activities have been allowed which will come into effect from 20th April, 2020. These limited exemptions will be operationalized by States/ UTs/ district administrations based on strict compliance to the existing guidelines. Also, before allowing these select additional activities, States/ UTs/ district administrations shall ensure that all preparatory arrangements with regard to the Standard Operating Procedures (SOPs) for social distancing in offices, workplaces, factories and establishments, as also other sectoral requirements are in place.
- ii. The consolidated revised guidelines incorporating these select permitted activities have been enumerated in paras 5-20 below.

4. Strict enforcement of the lockdown guidelines

- i. State/ UT Governments shall not dilute these guidelines issued under the Disaster Management Act, 2005, in any manner, and shall strictly enforce the same.
- ii. State/ UT Governments, may, however, impose stricter measures than these guidelines as per requirement of the local areas

5. All health services (Including AYUSH) to remain functional, such as:

- i. Hospitals, nursing homes, clinics, telemedicine facilities.
- ii. Dispensaries, chemists, pharmacies, all kinds of medicine shops including *Jan Aushadhi Kendras* and medical equipment shops.
- iii. Medical laboratories and collection centres.
- iv. Pharmaceutical and medical research labs, institutions carrying out COVID-19 related research.
- v. Veterinary Hospitals, dispensaries, clinics, pathology labs, sale and supply of vaccine and medicine.
- vi. Authorised private establishments, which support the provisioning of essential services, or efforts for containment of COVID-19, including home care providers, diagnostics, supply chain firms serving hospitals.
- vii. Manufacturing units of drugs, pharmaceuticals, medical devices, medical oxygen, their packaging material, raw material and intermediates.
- viii. Construction of medical/ health infrastructure including manufacture of ambulances.
- ix. Movement (inter and intra State, including by air) of all medical and veterinary personnel, scientists, nurses, para-medical staff, lab technicians, mid-wives and other hospital support services, including ambulances

6. Agricultural and related activities:

A. All agricultural and horticultural activities to remain fully functional, such as:

- i. Farming operations by farmers and farm workers in field.
- ii. Agencies engaged in procurement of agriculture products, including MSP operations.
- iii. 'Mandis' operated by the Agriculture Produce Market Committee (APMC) or as notified by the State/ UT Government (e.g., satellite *mandis*). Direct marketing operations by the State/ UT Government or by industry, directly



from farmers/ group of farmers, FPOs' co-operatives etc. States/ UTs may promote decentralized marketing and procurement at village level.

- iv. Shops of agriculture machinery, its spare parts (including its supply chain) and repairs to remain open.
- v. 'Custom Hiring Centres (CHC)' related to farm machinery.
- vi. Manufacturing, distribution and retail of fertilizers, pesticides and seeds.
- vii. Movement (inter and intra State) of harvesting and sowing related machines like combined harvester and other agriculture/ horticulture implements.

B. Fisheries - the following activities will be functional:

- i. Operations of the fishing (**marine and inland**)/ aquaculture industry, including feeding & maintenance, harvesting, processing, packaging, cold chain, sale and marketing.
- ii. Hatcheries, feed plants, commercial aquaria.
- iii. Movement of fish/ shrimp and fish products, fish seed/ feed and workers for all these activities.

C. Plantations- the following activities will be functional:

- i. Operations of tea, coffee and rubber plantations, with maximum of 50% workers.
- ii. Processing, packaging, sale and marketing of tea, coffee, rubber and cashew, with maximum of 50% workers.

D. Animal husbandry – the following activities will be functional:

- i. Collection, processing, distribution and sale of milk and milk products by milk processing plants, including transport and supply chain.
- ii. Operation of animal husbandry farms including poultry farms & hatcheries and livestock farming activity.
- iii. Animal feed manufacturing and feed plants, including supply of raw material, such as maize and soya.
- iv. Operation of animal shelter homes, including *Gaushalas*.

7. Financial sector: following to remain functional:

- i. Reserve Bank of India (RBI) and RBI regulated financial markets and entities like NPCI, CCIL, payment system operators and standalone primary dealers.
- ii. Bank branches and ATMs, IT vendors for banking operations, Banking Correspondents (BCs), ATM operation and cash management agencies.
 - a. Bank branches be allowed to work as per normal working hours till disbursement of DBT cash transfers is complete.
 - b. Local administration to provide adequate security personnel at bank branches and BCs to maintain social distancing, law and order and staggering of account holders.
- iii. SEBI, and capital and debt market services as notified by the Securities and Exchange Board of India (SEBI).
- iv. IRDAI and Insurance companies.



- 8. Social sector: following to remain functional:**
- i. Operation of homes for children/ disabled/ mentally challenged/ senior citizens/ destitutes/ women/ widows
 - ii. Observation homes, after care homes and places of safety for juveniles.
 - iii. Disbursement of social security pensions, e.g., old age/ widow/ freedom fighter pensions; pension and provident fund services provided by Employees Provident Fund Organisation (EPFO).
 - iv. Operation of *Anganwadis* – distribution of food items and nutrition once in 15 days at the doorsteps of beneficiaries, e.g., children, women and lactating mothers. Beneficiaries will not attend the *Anganwadis*.
- 9. Online teaching/ distance learning to be encouraged:**
- i. All educational, training, coaching institutions etc. shall remain closed.
 - ii. However, these establishments are expected to maintain the academic schedule through online teaching.
 - iii. Maximum use of Doordarshan (DD) and other educational channels may be made for teaching purposes.
- 10. MNREGA works to be allowed:**
- i. MNREGA works are allowed with strict implementation of social distancing and face mask.
 - ii. Priority to be given under MNREGA to irrigation and water conservation works.
 - iii. Other Central and State sector schemes in irrigation and water conservation sectors may also be allowed to be implemented and suitably dovetailed with MNREGA works.
- 11. Public utilities: following to remain functional:**
- i. Operations of Oil and Gas sector, including refining, transportation, distribution, storage and retail of products, e.g., petrol, diesel, kerosene, CNG, LPG, PNG etc.
 - ii. Generation, transmission and distribution of power at Central and State/ UT levels.
 - iii. Postal services, including post offices.
 - iv. Operations of utilities in water, sanitation and waste management sectors, at municipal/ local body levels in States and UTs.
 - v. Operation of utilities providing telecommunications and internet services.
- 12. Movement, loading/ unloading of goods/ cargo (inter and intra State) is allowed, as under:**
- i. All goods traffic will be allowed to ply.
 - ii. Operations of Railways: Transportation of goods and parcel trains.
 - iii. Operations of Airports and related facilities for air transport for cargo movement, relief and evacuation.
 - iv. Operations of Seaports and Inland Container Depots (ICDs) for cargo transport, including authorized custom clearing and forwarding agents.



- v. Operations of Land Ports for cross land border transportation of essential goods, including petroleum products and LPG, food products, medical supplies.
- vi. Movement of all trucks and other goods/ carrier vehicles with two drivers and one helper subject to the driver carrying a valid driving license; an empty truck/ vehicle will be allowed to ply after the delivery of goods, or for pick up of goods.
- vii. Shops for truck repairs and dhabas on highways, with a stipulated minimum distance as prescribed by the State/ UT authorities.
- viii. Movement of staff and contractual labour for operations of railways, airports/ air carriers, seaports/ ships/ vessels, landports and ICDs is allowed on passes being issued by the local authority on the basis of authorizations issued by the respective designated authority of the railways, airports, seaports, landports and ICDs.

13. Supply of essential goods is allowed, as under:

- i. All facilities in the supply chain of essential goods, whether involved in manufacturing, wholesale or retail of such goods through local stores, large brick and mortar stores or e-Commerce companies should be allowed to operate, ensuring strict social distancing without any restriction on their timing of opening and closure.
- ii. Shops (including *Kirana* and single shops selling essential goods) and carts, including ration shops (under PDS), dealing with food and groceries (**for daily use**), hygiene items, fruits and vegetables, dairy and milk booths, poultry, meat and fish, animal feed and fodder etc, should be allowed to operate, ensuring strict social distancing without any restriction on their timing of opening and closure.
- iii. District authorities may encourage and facilitate home delivery to minimize the movement of individuals outside their homes.

14. Commercial and private establishments, as listed below, will be allowed to operate:

- i. Print and electronic media including broadcasting, DTH and cable services.
- ii. IT and IT enabled Services, with upto 50% strength.
- iii. Data and call centres for Government activities only.
- iv. Government approved Common Service Centres (CSCs) at Gram Panchayat level.
- v. E-commerce companies. Vehicles used by e-commerce operators will be allowed to ply with necessary permissions.
- vi. Courier services.
- vii. Cold storage and warehousing services, including at ports, airports, railway stations, container Depots, individual units and other links in the logistics chain.
- viii. Private security services and facilities management services for maintenance and upkeep of office and residential complexes.



- ix. Hotels, homestays, lodges and motels, which are accommodating tourists and persons stranded due to lockdown, medical and emergency staff, air and sea crew.
 - x. Establishments used/ earmarked for quarantine facilities.
 - xi. Services provided by self-employed persons, e.g., electrician, IT repairs, plumbers, motor mechanics, and carpenters.
- 15. Industries/ Industrial Establishments (both Government and private), as listed below, will be allowed to operate:**
- i. Industries operating in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities.
 - ii. Manufacturing and other industrial establishments with access control in Special Economic Zones (SEZs) and Export Oriented Units (EoUs), industrial estates, and industrial townships. These establishments shall make arrangements for stay of workers within their premises as far as possible and/ or adjacent buildings and for implementation of the Standard operating protocol (SOP) as referred to in para 21 (ii) below. The transportation of workers to work place shall be arranged by the employers in dedicated transport by ensuring social distancing.
 - iii. Manufacturing units of essential goods, including drugs, pharmaceuticals, medical devices, their raw material and intermediates.
 - iv. Food processing industries in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities.
 - v. Production units, which require continuous process, and their supply chain.
 - vi. Manufacturing of IT hardware.
 - vii. Coal production, mines and mineral production, their transportation, supply of explosives and activities incidental to mining operations.
 - viii. Manufacturing units of packaging material.
 - ix. Jute industries with staggered shifts and social distancing.
 - x. Oil and gas exploration/ refinery.
 - xi. Brick kilns in rural areas i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities.
- 16. Construction activities, listed as below, will be allowed to operate:**
- i. Construction of roads, irrigation projects, buildings and all kinds of industrial projects, including MSMEs, in rural areas, i.e., outside the limits of municipal corporations and municipalities; and all kinds of projects in industrial estates.
 - ii. Construction of renewable energy projects.
 - iii. Continuation of works in construction projects, within the limits of municipal corporations and municipalities, where workers are available on site and no workers are required to be brought in from outside (in situ construction).
- 17. Movement of persons is allowed in the following cases:**
- i. Private vehicles for emergency services, including medical and veterinary care, and for procuring essential commodities. In such cases, one passenger besides the private vehicle driver can be permitted in the backseat, in case of



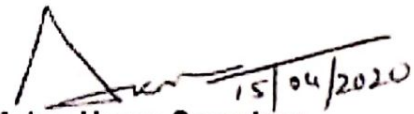
- four-wheelers; however, in case of two-wheelers, only the driver of the vehicle is to be permitted.
- ii. All personnel travelling to place of work and back in the exempted categories, as per the instructions of the State/ UT local authority.
- 18. Offices of the Government of India, its Autonomous/ Subordinate Offices will remain open, as mentioned below:**
- i. Defence, Central Armed Police Forces, Health and Family Welfare, Disaster management and Early Warning Agencies (IMD, INCOIS, SASE and National Centre of Seismology, CWC), National Informatics Centre (NIC), Food Corporation of India (FCI), NCC, Nehru Yuva Kendras (NYKs) and Customs to function without any restriction.
 - ii. Other Ministries and Departments, and offices under their control, are to function with 100% attendance of Deputy Secretary and levels above that. Remaining officers and staff to attend upto 33% as per requirement.
- 19. Offices of the State/ Union Territory Governments, their Autonomous Bodies and Local Governments will remain open, as mentioned below:**
- i. Police, home guards, civil defence, fire and emergency services, disaster management, prisons and municipal services will function without any restrictions.
 - ii. All other Departments of State/ UT Governments to work with restricted staff. Group 'A' and 'B' officers may attend as required. Group 'C' and levels below that may attend upto 33% of strength, as per requirement to ensure social distancing. However, delivery of public services shall be ensured, and necessary staff will be deployed for such purpose.
 - iii. District administration and Treasury (including field offices of the Accountant General) will function with restricted staff. However, delivery of public services shall be ensured, and necessary staff will be deployed for such purpose.
 - iv. Resident Commissioner of States/ UTs, in New Delhi, only to the extent of coordinating COVID-19 related activities and internal kitchen operations.
 - v. Forest offices: staff/ workers required to operate and maintain zoo, nurseries, wildlife, fire-fighting in forests, watering plantations, patrolling and their necessary transport movement.
- 20. Persons to remain under mandatory quarantine, as under:**
- i. All such persons who have been directed by health care personnel to remain under strict home/ institutional quarantine for a period as decided by local Health Authorities.
 - ii. Persons violating quarantine will be liable to legal action under Section 188 of the IPC, 1860.
 - iii. Quarantined persons, who have arrived in India after 15.2.2020, after expiry of their quarantine period and being tested Covid-19 negative, will be released following the protocol prescribed in the SOP issued by MHA.
- 21. Instructions for enforcement of above lockdown measures:**
- i. All the district magistrates shall strictly enforce the National COVID 19 directives as specified in **Annexure I**. Penalties prescribed shall be levied and collected from all persons and entities violating these directives.



- ii. All industrial and commercial establishments, work places, offices etc. shall put in place arrangements for implementation of SOP as in **Annexure II** before starting their functioning
- iii. In order to implement these containment measures, the District Magistrate will deploy Executive Magistrates as Incident Commanders in the respective local jurisdictions. The Incident Commander will be responsible for the overall implementation of these measures in their respective jurisdictions. All other line department officials in the specified area will work under the directions of such incident commander. The Incident Commander will issue passes for enabling essential movements as explained.
- iv. The Incident Commanders will in particular ensure that all efforts for mobilization of resources, workers and material for augmentation and expansion of hospital infrastructure shall continue without any hindrance.
- v. **Additional activities permitted in these guidelines shall be implemented in a phased manner, after making all arrangements necessary for strict implementation of the guidelines. These will come into force with effect from 20th April, 2020.**

22. Penal provisions

Any person violating these lockdown measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Sec. 188 of the IPC, and other legal provisions as applicable. Extracts of these penal provisions are at **Annexure III**.


15/04/2020
Union Home Secretary

National Directives for COVID-19 Management

The National Directives shall be enforced by the District Magistrate through fines and penal action as prescribed in the Disaster Management Act 2005.

PUBLIC SPACES

1. Wearing of face cover is compulsory in all public places, work places.
2. All persons in charge of public places, work places and transport shall ensure social distancing as per the guidelines issued by Ministry of Health and Family Welfare.
3. No organization /manager of public place shall allow gathering of 5 or more persons
4. Gatherings such as marriages and funerals shall remain regulated by the District Magistrate.
5. Spitting in public spaces shall be punishable with fine.
6. There should be strict ban on sale of liquor, gutka, tobacco etc. and spitting should be strictly prohibited.

WORK SPACES

7. All work places shall have adequate arrangements for temperature screening and provide sanitizers at convenient places.
8. Work places shall have a gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of staff, to ensure social distancing.
9. Persons above 65 years of age and persons with co-morbidities and parents of children below the age of 5 may be encouraged to work from home.
10. Use of Arogya setu will be encouraged for all employees both private and public.
11. All organizations shall sanitize their work places between shifts.
12. Large meetings to be prohibited.

MANUFACTURING ESTABLISHMENTS

13. Frequent cleaning of common surfaces and mandatory hand washing shall be mandated.
14. No overlap of shifts and staggered lunch with social distancing in canteens shall be ensured.
15. Intensive communication and training on good hygiene practices shall be taken up.

_____ 

Standard Operating Procedure for Social Distancing for Offices, Workplace, Factories and Establishments

The following measures shall be implemented by all offices, factories and other establishments:

1. All areas in the premises including the following shall be disinfected completely using user friendly disinfectant mediums:
 - a. Entrance Gate of building, office etc.
 - b. Cafeteria and canteens.
 - c. Meeting room, Conference halls/ open areas available/ verandah/ entrance gate of site, bunkers, porta cabins, building etc.
 - d. Equipment and lifts.
 - e. Washroom, toilet, sink: water points etc.
 - f. Walls/ all other surfaces
2. For workers coming from outside, special transportation facility will be arranged without any dependency on the public transport system. These vehicles should be allowed to work only with 30-40% passenger capacity.
3. All vehicles and machinery entering the premise should be disinfected by spray mandatorily.
4. Mandatory thermal scanning of everyone entering and exiting the work place to be done.
5. Medical insurance for the workers to be made mandatory.
6. Provision for hand wash & sanitizer preferably with touch free mechanism will be made at all entry and exit points and common areas. Sufficient quantities of all the items should be available.
7. Work places shall have a gap of one hour between shifts and will stagger the lunch breaks of staff, to ensure social distancing.
8. Large gatherings or meetings of 10 or more people to be discouraged. Seating at least 6 feet away from others on job sites and in gatherings, meetings and training sessions.
9. Not more than 2/4 persons (depending on size) will be allowed to travel in lifts or hoists.
10. Use of staircase for climbing should be encouraged.
11. There should be strict ban of gutka, tobacco etc. and spitting should be strictly prohibited.
12. There should be total ban on non-essential visitors at sites.
13. Hospitals/clinics in the nearby areas, which are authorized to treat COVID-19 patients, should be identified and list should be available at work place all the times.

Offences and Penalties for Violation of Lockdown Measures

A. Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005

51. Punishment for obstruction, etc.—Whoever, without reasonable cause

—
(a) obstructs any officer or employee of the Central Government or the State Government, or a person authorised by the National Authority or State Authority or District Authority in the discharge of his functions under this Act, or

(b) refuses to comply with any direction given by or on behalf of the Central Government or the State Government or the National Executive Committee or the State Executive Committee or the District Authority under this Act,

shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine, or with both, and if such obstruction or refusal to comply with directions results in loss of lives or imminent danger thereof, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years.

52. Punishment for false claim.—Whoever knowingly makes a claim which he knows or has reason to believe to be false for obtaining any relief, assistance, repair, reconstruction or other benefits consequent to disaster from any officer of the Central Government, the State Government, the National Authority, the State Authority or the District Authority, shall, on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

53. Punishment for misappropriation of money or materials, etc.—Whoever, being entrusted with any money or materials, or otherwise being, in custody of, or dominion over, any money or goods, meant for providing relief in any threatening disaster situation or disaster, misappropriates or appropriates for his own use or disposes of such money or materials or any part thereof or wilfully compels any other person so to do, shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, and also with fine.

54. Punishment for false warning.—Whoever makes or circulates a false alarm or warning as to disaster or its severity or magnitude, leading to panic, shall on conviction, be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine.

55. Offences by Departments of the Government.—(1) Where an offence under this Act has been committed by any Department of the Government, the head of the Department shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly unless he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.



(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a Department of the Government and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any officer, other than the head of the Department, such officer shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

56. Failure of officer in duty or his connivance at the contravention of the provisions of this Act.—Any officer, on whom any duty has been imposed by or under this Act and who ceases or refuses to perform or withdraws himself from the duties of his office shall, unless he has obtained the express written permission of his official superior or has other lawful excuse for so doing, be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine.

57. Penalty for contravention of any order regarding requisitioning.—If any person contravenes any order made under section 65, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.

58. Offence by companies.—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company or body corporate, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company, for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company, and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also, be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section— (a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and (b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

59. Previous sanction for prosecution.—No prosecution for offences punishable under sections 55 and 56 shall be instituted except with the previous sanction of the Central Government or the State Government, as the case may be, or of any officer authorised in this behalf, by general or special order, by such Government.

60. Cognizance of offences.—No court shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by— (a) the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised in this behalf by that Authority or Government, as the case may be; or (b) any person who has given notice of not less than thirty days in the manner prescribed, of the alleged offence and his intention to make a complaint to the National Authority, the State Authority, the Central Government, the State Government, the District Authority or any other authority or officer authorised as aforesaid.



B. Section 188 in the Indian Penal Code, 1860

188. Disobedience to order duly promulgated by public servant.—Whoever, knowing that, by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, he is directed to abstain from a certain act, or to take certain order with certain property in his possession or under his management, disobeys such direction, shall, if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury, or risk of obstruction, annoyance or injury, to any person lawfully employed, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to two hundred rupees, or with both; and if such disobedience causes or trends to cause danger to human life, health or safety, or causes or tends to cause a riot or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Explanation.—It is not necessary that the offender should intend to produce harm, or contemplate his disobedience as likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys, and that his disobedience produces, or is likely to produce, harm.

Illustration

An order is promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order, directing that a religious procession shall not pass down a certain street. A knowingly disobeys the order, and thereby causes danger of riot. A has committed the offence defined in this section.



AJAY BHALLA, IAS



गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
North Block,
New Delhi

D.O.No.40-3/2020-DM-I(A)

15th April, 2020

Dear Chief Secretary,

Hon'ble Prime Minister, in his address to the nation on 14th April, 2020 announced that the lockdown in India, which has been imposed to contain the spread of COVID-19 pandemic, will have to be extended till 3rd May, 2020. In pursuance of this announcement, Ministry of Home Affairs (MHA) issued an order dated April 14, 2020, copies of which have been communicated to you vide my earlier D.O. letter of even number dated 14th April, 2020.

2. Hon'ble Prime Minister, in his address, also announced the opening up of select necessary activities from 20th April, 2020. An order enclosing, the consolidated revised guidelines in this regard has been issued today, copy of which is enclosed.

3. With regard to the aforesaid order, the following is emphasized:

- i. The activities mentioned in the consolidated revised guidelines (Paras 5 to 20) will not be permitted in containment zones within hotspots, demarcated by the States/Union Territories/District Administrations as per guidelines of the Ministry of Health & Family Welfare (MoH&FW), Government of India.
- ii. If any new area is included in the category of containment zone, the activities allowed in that area till the time of its categorization as a containment zone, will be suspended, except for those activities which are specifically permitted under the consolidated revised guidelines.
- iii. The activities allowed under the consolidated revised guidelines will be withdrawn immediately, if any of the lockdown measures are violated, risking the spread of COVID-19. All entities, in the Government and private sectors, and members of public should follow the guidelines strictly.

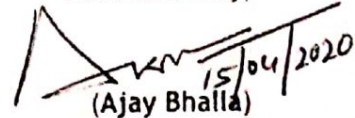
4. I have already emphasized vide my earlier D.O. letters of even number dated 31.03.2020 and 14th April, 2020, that States/Union Territories cannot dilute restrictions imposed vide the aforesaid guidelines issued by MHA. States / UTs may, however, impose stricter measures, than these guidelines as per requirement of the local areas.

5. I would again urge you to ensure compliance of the above instructions, and direct all concerned authorities for their strict implementation. You may also ensure that these guidelines are communicated to all the field agencies and wide publicity is given for the benefit of public.

With regards,

Encl: as above.

Yours sincerely,


(Ajay Bhalla) 15/04/2020

Chief Secretaries of All States
(As per standard list)

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 15th April, 2020

ORDER

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, has issued an Order dated 14th April, 2020 that the lockdown measures stipulated in the Consolidated Guidelines of Ministry of Home Affairs (MHA) for containment of COVID-19 epidemic in the country, will continue to remain in force upto 3rd May, 2020 to contain the spread of COVID-19 in the country;

Whereas, to mitigate hardship to the public, select additional activities will be allowed, which will come into effect from 20th April, 2020. However, these additional activities will be operationalized by States/ Union Territories (UTs)/ District Administrations based on strict compliance to the existing guidelines on lockdown measures. Before operating these relaxations, States/ UTs/ District Administrations shall ensure that all preparatory arrangements with regard to social distancing in offices, workplaces, factories and establishments, as also other sectoral requirements are in place. The consolidated revised guidelines incorporating these relaxations are enclosed;

Whereas, the consolidated revised guidelines will not apply in containment zones, as demarcated by States/ UTs/ District administrations. If any new area is included in the category of a containment zone, the activities allowed in that area till the time of its categorization as a containment zone, will be suspended except for those activities as are specifically permitted under the guidelines of Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW), Government of India;

Whereas, in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, 2005, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby issues directions to all the all Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/Union Territory Authorities for the strict implementation of enclosed consolidated revised guidelines.


15/04/2020
Union Home Secretary

To:

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
(As per list attached)

Copy to:

- i. All members of the National Executive Committee.
- ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.

No. 40-3/2020-DM-I(A)
Government of India
Ministry of Home Affairs

North Block, New Delhi-110001
Dated 16th April, 2020

ORDER

In continuation of Ministry of Home Affairs's Order No. 40-3/2020-DM-I(A) Dated 15th April, 2020 and in exercise of the powers, conferred under Section 10(2)(l) of the Disaster Management Act, the undersigned, in his capacity as Chairperson, National Executive Committee, hereby orders to include the following in the consolidated revised guidelines for strict implementation by Ministries/ Departments of Government of India, State/Union Territory Governments and State/ Union Territory Authorities:

- I. **Sub-clause (viii) under Clause 6 'A' on All Agricultural and horticultural activities:**
 - viii. Collection, harvesting and processing of Minor Forest Produce (MFP)/ Non Timber Forest Produce (NTFP) by Scheduled Tribes and other forest dwellers in forest areas.
- II. **Sub-clause (iii) under Clause 6 'C' on on Plantations:**
 - iii. Bamboo, Coconut, Arecanut, Cocoa, spices plantation and their harvesting, processing, packaging, sale and marketing.
- III. **Sub clause (v) & (vi) under Clause 7 on Financial Sector:**
 - v. Non-Banking financial institutions (NBFCs) including Housing Finance Companies (HFCs) and Micro Finance Institutions (NBFC-MFIs) *with bare minimum staff.*
 - vi. Cooperative Credit Societies.
- IV. **Clause 16 (i) on construction activities in rural areas, includes, water supply and sanitation; laying/erection of power transmission lines and laying of telecom optical fiber and cable along with related activities.**


Home Secretary 16/04/2020

To

1. The Secretaries of Ministries/ Departments of Government of India
2. The Chief Secretaries/Administrators of States/Union Territories
(As per list attached)

Copy to:

- i. All members of the National Executive Committee.
- ii. Member Secretary, National Disaster Management Authority.